को अनावश्यक दौड़-भाग नहीं करनी पड़ रही है. इसने उद्यमियों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की एक अलग छवि बनाई है.''
लघु उद्योगों को तकनीकी जानकारियां मुहैया कराने के लिए एमएसएमई विभाग ने ''डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी'' (एकेटीयू) के साथ एमओयू किया है. एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक बताते हैं, ''विश्वविद्यालय से जुड़े 756 कॉलेजों के विद्यार्थी न केवल ओडीओपी योजना से जुड़ेंगे बल्कि इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेंगे.''

▲ **छोटों को बड़ी मदद** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की मौजूदगी में उद्यमियों को ऋण वितरित

संकट में सहारा बने छोटे उद्यम

कोविड-19 के खिलाफ जंग में एमएसएमई ने यूपी को सहारा दिया है. 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुए महज एक हफ्ता ही हुआ था कि देश भर में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और इलाज में लगे डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए जरूरी 'पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट' (पीपीई) किट की कमी महसूस होने लगी थी. यूपी में भी कोरोना संक्रमण के मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे थे. लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल की सुबह अपनी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम-11 के बैठक में यूपी में ही पीपीई किट और वेंटिलेटर जैसे जरूरी उपकरणों के निर्माण की योजना बनाने को कहा. इसके बाद एमएसएमई विभाग हरकत में आ गया. विभाग के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और अपर मुख्य सचिव सहगल ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके योजना का खाका खींचा. अगले दिन योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई. उनकी अनुमति मिलते ही यूपी को पीपीई किट के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की योजना को हकीकत में बदलने के प्रयास शुरू हो गए. सहगल ने प्रदेश में काम कर रहे टेक्सटाइल से जुड़े उद्यमियों से संपर्क किया और उन्हें पीपीई किट निर्माण करने को प्रेरित किया. लॉकडाउन में इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को उनके गांव से लाने की व्यवस्था हुई. युद्ध स्तर पर कच्चे माल का इंतजाम हुआ. सभी उद्यमियों को स्टैंडर्ड पीपीई किट बनाने का प्रोटोकॉल समझाया गया. 5 अप्रैल को नोएडा, कानपुर और उन्नाव में आधा दर्जन टेक्सटाइल फैक्ट्रकयों ने पीपीई किट का उत्पादन शुरू किया. आज यूपी में कुल 53 फैक्ट्रयों ने 50 हजार पीपीई किट रोज बनाने की क्षमता हासिल कर ली है. यूपी में कोविड के इलाज में लगे मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में बड़ी संख्या में प्रदेश में बनने वाली पीपीई किट का उपयोग हो रहा है. प्रदेश सरकार ने यूपी में वेंटिलेटर बनाने वाली नोएडा की एकमात्र इकाई को पुनर्संचालित करने में सहयोग किया है. यह इकाई अब रोज 300 वेंटिलेटर का उत्पादन की क्षमता हासिल कर पूरे देश में इसकी आपूर्ति कर रही है.

आसान हुआ उद्योग लगाना

एमएसएमई के जरिए यूपी में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं पैदा करने और औद्योगिक विकास का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाए. इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) के यूपी चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष सुनील वैश्य बताते हैं, ''प्रदेश में नई एमएसएमई लगाने के लिए 29 विभागों से करीब 80 अनुमतियां लेनी पड़ती हैं. उद्यमी कम से कम छह महीने आधा दर्जन विभागों से अनुमति पाने के लिए चक्कर लगाता रहता है.'' एमएसएमइ उद्योगों की स्थापना में लाल फीताशाही को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने 18 अगस्त को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन के जरिए ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020'' को मंजूरी दी है. इस नए ऐक्ट के तहत यह व्यवस्था की जा रही है कि जिला उद्योग केंद्र में उद्यमी के निर्धारित प्रपत्र जमा कराने पर 72 घंटे के भीतर स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा. इस प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद इकाई को 900 दिन तक किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और वह तत्काल अपना उद्यम शुरू कर सकेगा.

सहगल बताते हैं, ''नए अधिनियम के माध्यम से एक वर्ष में 5 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें ध्यान रखा गया है कि उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके.'' निजी इकाइयों और एमएसएमई विभाग के बीच मामले सुलझाने के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल का प्रावधान है लेकिन वर्तमान में एक ही फैसिलिटेशन काउंसिल होने के कारण एमएसएमई के काफी मामले लंबित हैं. नए ऐक्ट में मंडल स्तर पर इस तरह की फैसिलिटेशन काउंसिल बनाने का प्रस्ताव है. इससे मंडल स्तर पर एमएसएमई की समस्याओं का मंडलायुक्त की अध्यक्षता में फैसिलिटेशन काउंसिल में निराकरण प्राथमिकता के तौर पर किया जा सके.

कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसके दुष्परिणाम से निबटने के लिए राज्य सरकार अगर एमएसएमई के ढांचे को मजबूत करने में कामयाब हुई तो वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. ■

''नए अधिनियम के माध्यम से एक वर्ष में 5 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें ध्यान रखा गया है कि उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके''
नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव